मुख्यमंत्री आज से 3 दिन शेखावाटी का दौरा करेंगे

वे जयपुर, सीकर, झुँझुनूँ जिले में जनता से सीधे संवाद करेंगे, अधिकारियों की मीटिंग लेंगे

जयपुर, 18 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शर्मा आम जन से संवाद करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठकें लेंगे।

शर्मा शनिवार को सड़क मार्ग से टांटियावास, चौमूं, गोविन्दगढ़, सरगोठ, रींगस, पलसाना, बाजौर होते हुए, सीकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहाँ वे जनसुनवाई करेंगे तथा अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके पश्चात वे धोद, लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर जाएंगे।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 अप्रेल को पिलानी में यमुना जल समझौते की डीपीआर के लिये गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

मुख्यमंत्री रविवार को मण्डावा और मुकुन्दगढ़ के रास्ते झुंझुनूं जाएंगे तथा वहाँ के सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे। झुंझुनूं से मुख्यमंत्री गुढ़ा मोड़, बगाड़, चिड़ावा के रास्ते पिलानी जाएंगे। सोमवार को शर्मा बिट्स पिलानी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहाँ से हवाई मार्ग से मलसीसर पहुंचेंगे, जहां पेयजल के डैम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे चूरू पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

चूरू से मुख्यमंत्री हिण्डाला फार्म हाउस, प्रेमपुरा (सीकर) जाएंगे, जहां वे स्व. ईश्वर राम हिण्डाला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद चौरू, फागी (जयपुर) पहुंचेंगे और भक्त शिरोमणि धन्ना भगत की 610वीं जयन्ती महोत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा 20 अप्रेल को पिलानी में यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे नक्शे एवं अलाइन्मेन्ट की डिजाइन पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

उल्लेखनीय है कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है।

'मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है'

मालदा (पश्चिम बंगाल), 18 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा- मैंने शिविर में रह रहे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उनकी शिकायतें सुनीं और भावनाओं को समझा।

■ ममता बनर्जी के अनुरोध को ठुकरा कर राज्यपाल शनिवार को मुर्शिदाबाद जायेंगे।

राज्यपाल शनिवार को मुर्शिदाबाद जाएंगे। उन्होंने कहा- मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ, चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे।

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा था मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। बोस ने कहा, बंगाल में अलग-अलग जगहों से हिंसा की भयावह खबरें आ रही हैं। हमें हिंसा के पंथ को ताबूत में बंद कर ताबूत में आखिरी कील भी ठोकनी होगी। बंगाल में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है।

यूनेस्को के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के "मैमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर" में शामिल किया जाना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान किया जाना है।

पार्टी अध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सब महत्वपूर्ण नहीं है तथा आरएसएस का कोई स्वयंसेवक ही संघ की विचारधारा एवं विचार-प्रक्रिया को कायम रख सकता है तथा पार्टी को इसे जारी रखने की जरूरत है। अमित शाह की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले भूपेन्द्र यादव आरएसएस को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वे संघ के पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं। ऐसे ही और कुई मुद्दों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए जबरदस्त परामर्श एवं चर्चाएं जारी हैं।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के खतरों के बीच टैस्ला के शेयरों में भारी गिरावट आई है, विशेषरुप से कैनडा द्वारा कंपनी को इलैक्ट्रिक वाहन सब्सिडी से बाहर किए जाने के बाद। संभावना है कि यू.के. भी ऐसा ही कदम उठाएगा।

लेकिन, भारत में स्टारलिंक की योजनाएं सही दिशा में बढ़ती नज़र आ रही हैं। बुधवार को उद्योगमंत्री गोयल ने स्टारलिंक के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की, जिसमें कंपनी के वाइस प्रैसिडैंट चैड गिब्स और सीनियर डायरैक्टर रायन गुडनाइट शामिल थे। भारतीय टैलिकॉम कंपनियाँ, भारती एयरटैल और वोडाफोन आइडिया प्रमुख हैं, स्टारलिंक के साथ भारत में सैटेलाइट आधारित टैलिकॉम सेवाओं की शरुआत को लेकर पार्टनशिप पर बातचीत कर रही हैं।

सैटलाइट इन्टरनैट को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना सरकार की व्यापक डिजिटल इन्क्लूज़न रणनीति के अनुरुप है। दूरसंचार मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में सैटलाइट संचार की महत्ता पर जोर दिया था, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, जहाँ, फाइबर और मोबाइल नैटवर्क जैसे पारंपरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पहुँचना मुश्किल है।

उप मु.मंत्री एकनाथ शिंदे, अमित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकत की परीक्षा होंगे।

मुंबई में फड़नवीस, ठाकरे की शिवसेना से सीधी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जबकि, ठाणे और कल्याण डोंबिविली क्षेत्रों में शिंदे के प्रभाव की परीक्षा होगी, जहाँ उनकी प्रतिस्पर्धा, ना केवल यूबीटी से बल्कि अपने ही भाजपा सहयोगियों, दोनों से है। पुणे और पिंपरी -चिंचवड़ जैसे क्षेत्रों में, जहाँ अजित पवार का एनसीपी गुट हावी है, वहाँ शिंदे की स्थिति की स्थिति कमज़ोर मानी जा रही है।

मुंबई के एक राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, "शिंदे मुश्किल स्थिति में हैं। उन्हें इन चुनावों के जरिए अपने गुट की ताकत साबित करनी है, लेकिन, गठबंधन की अंदरुनी खींचतान इसमें बाधा बन रही है।"

महायुति के दांव बहुत ज्यादा है। नगर निगमों पर नियंत्रण स्थानीय प्रशासन को प्रभाति करता है और व्यापक राजनैतिक ताकत का संकेत होता है। नगर निगम चुनावों में कमज़ोर प्रदर्शन विपक्ष को ताकत देगा खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस को शहरी क्षेत्र में जहां मतदाता सड़क व पेयजल आपूर्ति जैसे मुद्दों से प्रभाति होते हैं।

इसी बीच रायगढ़ विवाद गठबंधन के सत्ता संघर्ष को दर्शाता है। शाह का एनसीपी की प्रति झुकाव भाजपा के रणनीतिक समीकरणों के हिसाब किताब को दर्शा रहा है।

चुनाव की उलटी गिनती शुरु हो रही है और महायुति को आन्तरिक मतभेदों को सुलझाना ही होगा ताकि एक प्रभावी चुनाव अभियान चलाया जा सके। राजनैतिक विश्लेषक कहते है कि ठाकरे की सरकार को गिराने के कारण शिंदे की सौदेबाजी की ताकत अब कम होती जा रही है। एक सूत्र ने बताया कि, शिंदे ने शाह को अपने पूर्व योगदान की याद दिलाई पर भाजपा उन्हें कुछ भी देने के मूड में नहीं है। आगामी सप्ताओं में पता चलेगा कि शाह इन मतभेदों को सुलझाकर कोई समझौता कर पाते या फिर महायुति की फूट महाराष्ट्र के राजनैतिक भविष्य को नया आकार देगी।

दो हजार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भुगतान पर एमडीआर हटा चुका है।

मंत्रालय ने कहा है, चूंकि वर्तमान में यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर लगाया ही नहीं जाता है, ऐसे में इन लेन-देन पर कोई जीएसटी लागू ही नहीं किया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाँग्लादेश, मुर्शिदाबाद के दंगों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई थीं। हिन्दुओं को हर तरह से डराया-धमकाया गया था, खुली धमकियाँ दी गई थीं तथा उन पर हमले किये गये थे। बाँग्लादेश में हिन्दू मंदिरों तथा सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया तथा उन्हें नष्ट कर दिया गया। ढाका के सुप्रसिद्ध इंडियन इन्फॉर्मेशन सेन्टर, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, को उन्मादी भीड़ पूरी तरह ढहा दिया।

अब, बाँग्लादेश ने बंगाल के सीमान्त जिले मुर्शिदाबाद में तबाही मचा दी है, उसे साम्प्रदायिक उन्माद का ग्रास बना दिया है।

वस्तुतः मुर्शिदाबाद में हिन्दू निवासियों के खिलाफ हिंसा हो रही है, तथा जिले के हिन्दू परिवार बड़ी संख्या में अपने घर-गांव छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। यह एक विडम्बना ही है कि एक हिन्दू -बहुल देश के एक राज्य के एक हिस्से से हिन्दू घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गये हैं। इस स्थिति को हलके में लेते हुये, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि संदर्मित लोग एक जिले से दूसरे जिले में ही तो गये हैं, देश के अन्य भागों में शरण पाने के लिये वे राज्य छोड़कर तो नहीं गये हैं। उक्त नेता, जो स्वयं बिहार छोड़कर बंगाल में आ बसे हैं, अपने हिसाब से, एक बड़ा सांत्वनाप्रद बयान देकर, बुराई में अच्छाई ढूंढने की निरर्थक कोशिश मात्र कर रहे हैं।

बंगाल के सभी जिलों में मुस्लिमों द्वारा एकाएक की गई हिंसा तथा मुस्लिम इलाकों हिन्दुओं के जान-माल के नुकसान से एकाएक चौंक पड़ी ममता बनर्जी अब इसे राजनीति का परिणाम बताने की कोशिश कर रही हैं।

ममता ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना शुरु कर दी है तथा आरोप लगाया है कि राज्य के साम्प्रदायिक उन्माद के लिये शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये उपद्रव पूर्व-नियोजित थे तथा आतंक का माहौल पैदा करने के लिये पड़ोसी बाँग्लादेश से लोग बंगाल में घुस आये थे। जैसी कि उनकी आदत है, उन्होंने राज्य की वर्तमान दुर्दशा पर हो रही चर्चा की दिशा बदलने के लिये, उसे पूरी तरह से असम्बंधित मुद्दों की ओर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पक्ष के इमामों की एक सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि मोदी के बाद, शाह का भविष्य क्या होगा। वे मुस्लिमों को अपनी तरफ बनाये रखने की हताशापूर्ण कोशिश कर रही हैं।

हिंसा इतनी प्रचंड रही है कि पहले की स्थितियों के विपरीत, राज्य की पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और यह बल प्रयोग शांति कायम करने के लिये नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा के लिये किया गया था। पुलिस की सम्पत्तियाँ तो नष्ट की ही गई हैं, पुलिस पर हमले भी किये गये हैं। इस कारण, पुलिस लाठीचार्ज करने तथा फायरिंग के लिये मजबूर हो गई। इससे उनके मुस्लिम समर्थकों में उनकी स्थिति खराब हो गई तथा कुछ मुस्लिम मंत्रियों ने तो राज्य पुलिस की आलोचना तक की है। इसके अलावा, कुछ मुस्लिम पोलिटिकल पार्टियाँ, मुस्लिम वोटों पर ममता की निर्विवाद पकड़ को एक तरफ रखते हुये, अल्पसंख्यकों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत तथा एकजुट कर रही हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ ने बच्चों को अपनी पकड़ में ले लिया था तथा उनसे ईंट-पत्थर और मिसाइलें फिंकवाई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएफ ने घुसपैठियों को अंदर आने दिया तथा इस प्रकार, इस उपद्रव के लिये केन्द्र जिम्मेदार है।

बीएसएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है तथा इस प्रकार, उपद्रवों को मिसहैन्डल करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीएसएफ ने ईंट-पत्थर फैंकने के लिये छोटे-छोटे बच्चों को पैसे दिये थे। राज्य प्रशासन की पोल पूरी तरह खुल गई है तथा वह हिंसा को रोकने में असफल रहा है। दूसरी और, बीएसएफ पर फायरिंग करने का दोषारोपण किया जा रहा है तथा कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गये हैं।

बाइस नक्सलियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि जिले में लगातार नक्सल उनमूलन अभियान चलाया जा रहा है। पुनर्वास नीति का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

'नियद नेल्लानार योजना' के तहत विकास कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर नौ महिला समेत 22 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेंडर किया है।

अमेरिका तीन सप्ताह में ही, जल्दी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम्पनियों की अमेरिकी बाज़ार में अच्छी खासी उपस्थिति है, में राहत चाह रहा है। इसके बदले में अमेरिका, भारत के डेयरी, पोल्ट्री और डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में अधिक पहुँच चाहता है। वार्ताओं का रणनीतिक महत्व बहुत विस्तृत है, जिससे ये और ज्यादा जटिल हो गई हैं। इनसे ग्लोबल सप्लाई चेन का पुनर्गठन प्रभावित होगा, जो वर्तमान में चीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है।

अमेरिकन अधिकारियों को कुछ ही सप्ताह में भारत के साथ समझौता फाइनल होने की उम्मीद है। लेकिन गोयल ने संयमित रुख अपनाया और संकेत दिया कि 6 माह में संपूर्ण समझौता हो सकता है। असल मुद्दों की जटिलता और इसके स्थानीय स्तर पर पड़ने वाले राजनैतिक प्रभाव के कारण नई दिल्ली को मजबूरन सतर्क व संतुलित कूटनीति अपनानी पड़ रही है। मूल रूप से सभी व्यापारिक गतितिविधयाँ टैरिफ या बाज़ार तक पहुँच से संबंधित नहीं हैं।

यह सोचा समझा भू-राजनैतिक खेल है। ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य अनौपचारिक आर्थिक गठबंधन बनाना है, जो वैश्विक सप्लाई चेन की चीन पर निर्भरता कम कर सके और टैक्नॉलजी, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों व निर्माण क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती दे सके।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908